प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

06.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 के दौरान नाबार्ड से 7 सौ 13 करोड़ 87 लाख रूपए की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। आज शिमला में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले सत्र में आयोजित ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन स्वीकृत योजनाओं में 5 सौ 12 करोड़ 31 लाख रूपए की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोकनिर्माण विभाग जबकि 2 सौ एक करोड़ 56 लाख रूपए की जलशक्ति विभाग की हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से राज्य को करीब 50 हजार करोड़ रूपए का नुकसान होगा और ऐसे में सरकार को प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। बैठक में तीनों जिलों के विधायकों ने अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित मांगे रखीं।

बीजेपी–ज्ञापन

भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार पर विपक्षी विधायकों की पिछली प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने और विधायक निधि रोकने का आरोप लगाते हुए आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रातप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अक्तूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिससे विधायकों को अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने में मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से विपक्षी विधायकों द्वारा दी गई विकास प्राथमिकताओं पर न तो डीपीआर बनाई जा रही है और न ही उन्हें नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और समान विकास की भावना के विपरीत है।

सुक्खू

भाजपा विधायकों द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने कहा कि अच्छा होता अगर भाजपा विधायक दल प्रदेश के लिए रुके राजस्व घाटा अनुदान–आरडीजी की बहाली के लिए राज्यपाल के पास जाता और हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करता।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है और इस संदर्भ में सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि

सरकार ने आर.डी.जी. को लेकर 16वें वित आयोग और वित्त मंत्री के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा है।

विशेष सत्र मैंने हिमाचल हिमाचल प्रदेश की जनता के हित को लेकर बुलाया गया। स्पेशल ग्रांट हमें आरडीजी के रूप में मिलती थी वह 72 साल बाद बंद। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमें सहयोग चाहिए और इसलिए विशेष सत्र में वो अपनी बात रखें जो जनता के पास वो बात अपनी रख रहे हैं वो गलत बात रख रहे हैं। आरडीजी 17 राज्यों की बंद करने का फैसला हिमाचल के हितों के साथ कुठाराघात है। प्रदेश को नुकसान होगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हिमाचल के संदर्भ के पैमाने अलग होने की और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि सही ढंग से पक्ष नहीं रखा। 4 बार वित्त मंत्री से मैं पक्ष रखने को नहीं मिला? चार बार वित्त आयोग के चेयरमैन पनगड़िया से पक्ष रखने को मैं नहीं मिला?

राज्यपाल

नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले प्रदेश के एनसीसी कैडेटस ने आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से लोक भवन शिमला में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कैडेटस को सम्मानित किया और राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने पर उन्हें बधाई दी। राज्यपाल से भेंट के दौरान कैडेटस ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य के 21 एन.सी.सी. कैडेटस ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर अपनी प्रतिभा अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस वर्ष गणतंत्र दिवस शिविर में बालिका कैडेटस की संख्या अधिक होने पर खुशी जताई।